

Research Papers



महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान –
एक अध्ययन

डॉ. रेखा आचार्य
रीडर, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

मंजुला भालसे
पीएच.डी. शोधार्थी,
डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान,
डोंगरगांव, महु, म.प्र.

प्रस्तावना :-

हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रीय संविधान लागू हुआ तथा स्वतंत्र भारत में सभी वर्गों के लिये खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति तथा उनके सामाजिक विकास के लिये विशेष प्रयास किये गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही शासन ने महिलाओं के कल्याण की चिंता की है। यद्यपि इस उद्देश्य के लिये क्या एवं कैसी मदद की जाये, इसके बारे में विचारों की परिणती आती रही है।

भारत में महिला आर्थिक विकास का तात्पर्य ! स्वआत्मविश्वास स्वनिर्णय एवं समाज में भागीदारी से है। अतः यदि महिला सुशिक्षित है तथा आर्थिक सम्पन्नता लिये हुए है, तो उसके विकास के मार्ग अपने आप खुल गये हैं।

महिलाओं के विकास के आधारभूत मानदंडों में अब सरकारी दृष्टिकोण में भी काफी बदलाव आया है। जहां स्वतंत्रता प्राप्ति से वह कल्याण और विकास के सवाल में उलझी थी, आज वही महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रयासों को तेजी देने के लिए तैयार है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकास प्रक्रिया में समान साझेदार एवं प्रतिभागी के रूप में महिलाओं पर विशेष बल देते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ी है।

आज वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ है, जिसमें महिला जनसंख्या 49,57,50,000 होने का अनुमान है। यह देश की कुल आबादी का 48.3 प्रतिशत है। भारत में 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में 30.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 11.5 प्रतिशत महिलाएं कार्यशील हैं। 2001 में काम में महिलाओं की भागीदारी 25.7 प्रतिशत है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में "महिला घटक योजना" को प्राथमिकता दी गयी है। सातवीं योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं हेतु 27 लाभार्थी उन्मुख स्कीमों की संकल्पना शुरू हुई। योजना के प्रारूप में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया गया है, विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ महिलाओं के विशेष कार्यक्रम चलाए गए।

विगत पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का प्रादुर्भाव तो हुआ, लेकिन उसका सही तरीके से चयन नहीं किया गया। महिलाओं की आर्थिक सक्षमता को मूर्त रूप देने हेतु भारत में विगत एक दशक से राष्ट्रीयकृत बैंक आगे आए जिस कारण से बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की उपलब्धता सुविधाजनक हो गई है। लेकिन इस सुविधा का लाभ महिलाये अपने विकास में कितना कर पा रही हैं, यह कहना मुश्किल है।

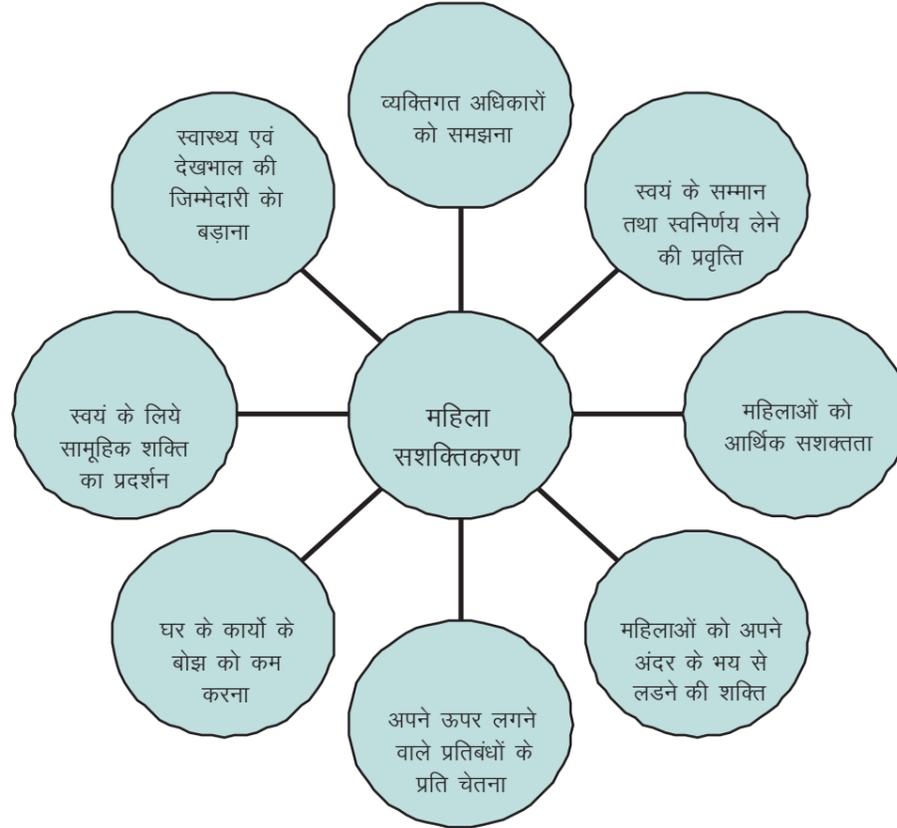
विश्व के विकसित राष्ट्रों में तो दूसरे महायुद्ध के बाद से ही महिला स्वरोजगार का विकास हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा व इंग्लैंड में छोटे उद्योगों का 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की बागडोर महिला उद्यमियों के हाथों में है। ये महिलाएं विशेष रूप से खुदरा व्यापार, रेस्टोरेंट, शिक्षा सफाई व निर्माण उद्योग में कार्यरत हैं। वे महिलाएं निम्न कारणों से अपने व्यवसाय में सफल रही हैं।

1. ये नवपर्वतन व प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में अपनी योग्यता प्रमाणात्मकता करना चाहती हैं।
2. उन्हें आत्म संतुष्टि हेतु चुनौतीपूर्ण अवसरों की तलाश थी।

इस प्रकार जहां कि एक तरफ पश्चिमी महिला आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाकर आत्म विश्वास व आत्म गौरव प्राप्त कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। तथा अर्थोपार्जन के लिये घर से बाहर निकलने को उसकी गृहलक्ष्मी की भूमिका के लिये दुर्भाग्यपूर्ण चुनौती माना जाता है।

नारी की परम्परागत छवि भी उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता है लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है। यही कारण है कि महिला उद्यमिता के विकास के लिये अब तक जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे वस्तुतः महिला उत्थान के कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

Please cite this Article as : मंजुला भालसे and डॉ. रेखा आचार्य , महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान –
एक अध्ययन : Indian Streams Research Journal (MAY ; 2012)



उद्देश्य

1. बैंकों द्वारा महिलाओं को दिये जाने वाले ऋणों की उपलब्धता का अध्ययन।
2. महिलाओं के आर्थिक विकास में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण के प्रभावों का अध्ययन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं द्वारा ऋण प्राप्त के उपरान्त भुगतान स्थिति का अध्ययन।
4. अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा महिलाओं को दिये जाने वाले ऋण में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना।

प्रविधि

वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिये निम्न वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है, उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता किस विधि या तरीके को अपनाता है, उसे प्रविधि कहते हैं, प्रविधि वह साधन है, जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिये आवश्यक वास्तविक तथ्यों सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है।

उपकल्पना

1. पारिवारिक भार एवं सामाजिक कारणों से महिलाएं बैंकों की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है।
2. अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण महिलाएं बैंक योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है।
3. योजनाओं की प्रचार-प्रसार की कमी के कारण महिलाओं को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, इसलिए महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है।

बैंक का इतिहास :-

प्राचीन समय में राजा-महाराजाओं, नवाबों अथवा विभिन्न वर्गों के शासकों को समय-समय पर उधार लेने की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये वह अपने राज्यों में साहूकारों को बसाते थे, उन्हें भूमि देते थे तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे। यही सेठ, साहूकार लोग जनता से भी रकम जमा कर लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर किसानों तथा अन्य व्यक्तियों को ऋण सुविधायें प्रदान करते थे, यही व्यक्ति उस समय बैंक कहे जाते थे। इसलिए वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीनकाल में बैंक आधुनिक प्रकार के नहीं थे, तथापि महाजन, सुनार, सर्राफा आदि यह कार्य किया करते थे, भारत यूनान, बेबीलोन में यह कार्य मंदिर के पुजारी किया करते थे। एक मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत बेबीलोन में हुई तत्पश्चात अन्य देशों जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड में विकास हुआ। 19 वीं शताब्दी में औद्योगिक प्रगति भी बैंक के विकास का कारण बनी।

संक्षिप्त परिचय

बैंक तथा उनकी शाखाये अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी, रक्तवाहिनियों की तरह है, जो समय-समय पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जीवन प्रवाह बनाये रखती है। बैंकों हिन्दी में अधिकोष है, लेकिन बोलचाल और व्यवहार में बैंक ज्यादा लोकप्रिय शब्द बन गया है। आधुनिक बैंकिंग का विकास यूरोप में हुआ, जब इटली में 1146 में प्रथम बैंक – बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक बैंक स्थापित हुए। बैंकिंग इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना है। इसके बाद विकास क्रम चलता रहा और 18 वीं शताब्दी के अन्त तक बैंकिंग कार्य मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के द्वारा किया जाने लगा। अब बैंक प्रणाली विश्व के सभी देशों में इतनी विकसित है कि बैंक वर्तमान आर्थिक प्रणाली व्यापार उद्योग व्यवस्था का अनिवार्य अंग है।

परिभाषाएँ

बैंकों को अनेक दृष्टिकोणों से परिभाषित किया गया है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में संक्षेप में बैंक एक व्यक्ति या संस्था हो सकती है, जो मुद्रा और साख का व्यापार (क्रय-विक्रय या लेन-देन) करती है। वर्तमान में आधुनिक बैंक संस्थाओं के दो स्वरूप हैं। 1. व्यापारिक बैंकिंग

2. विनियोग**बैंकों की कार्य प्रणाली**

वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक के कार्यों को चार भागों में बांटा जा सकता है—

1. जमा अथवा निक्षेप स्वीकार करना।
2. ऋण अथवा उधार देना।
3. एजेंट के रूप में कार्य
4. विविध कार्य

जमा अथवा निक्षेप स्वीकार करना आधुनिक बैंक का कार्य है। अतः इसके लिये वह समाज के सभी वर्गों से जमा प्राप्त करने में रुचि रखता है। जमा राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। ये राशि आर्थिक विकास में सहायक होती है, व्यापारिक बैंक प्रायः 4 प्रकार के खातों को जमा करने की सुविधा देता है।

बैंकों के प्रकार

1. **भारतीय रिजर्व बैंक** – भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित देश का केन्द्रीय बैंक है, जो बैंकिंग प्रणाली में केन्द्रीय स्थान रखता है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, करेंसी नोटों का निर्गमन करना भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं।
2. **व्यापारिक बैंक** – बैंक शब्द प्रायः व्यापारिक बैंकों के लिये ही प्रयोग किया जाता है। बैंकों का कार्य जनता से जमा स्वीकार करके, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ऋण व अग्रिम देना है।
3. **औद्योगिक बैंक** – ये बैंक उद्योगों के निर्माण, विस्तार, विकास, बड़ी मशीनों या प्लांट की खरीद, आधुनिकीकरण आदि कार्यों के लिये बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
4. **विदेशी विनियम बैंक** – ये बैंक मुख्यतः विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय विदेशी व्यापार तथा विदेशी भुगतानों को निपटाने की व्यवस्था करते हैं। कुछ भारतीय बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि भी विदेशी विनियम बैंक का कार्य करते हैं।
5. **कृषि बैंक** – भारत में ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु दूसरी महत्वपूर्ण एवं शीर्ष बैंक है। 1982 में स्थापित कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक जिसे संक्षेप नाबार्ड (छ।ठ।त्व) कहते हैं। इस बैंक की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई तथा इसके गठन के लिये रिजर्व बैंक के कृषि साख विभागाध्यक्ष कृषि प्रवर्तित एवं विकास निगम का विलय कर दिया गया। इस बैंक की स्थापना गांवों में कृषि, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग व अन्य ग्रामीण दस्तकारी और सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिये की गई।
6. **सहकारी बैंक** – ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं तथा शहरी क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योग भवन निर्माण, छोटे व्यवसाय, परिवार तथा उपभोक्ता की आवश्यकताओं आदि के लिये सहकारिता सिद्धान्त पर आधारित सहकारी बैंक, अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं तथा सदस्यों से तथा नागरिकों से उनकी बचतों जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। सहकारी संस्थाओं का संगठन त्रिस्तरीय होता है – प्राथमिक संस्थाएं, केन्द्रीय (जिला) सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक।
7. **भूमि केन्द्रीय बैंक** – प्रत्येक देश में सच्ची बैंकिंग प्रणाली को नियन्त्रण, नियमित तथा निर्देशित करने के लिये लगभग प्रत्येक देश का एक प्रमुख शीर्ष बैंक होता है, जिसे उसे देश का केन्द्रीय बैंक कहते हैं। जैसे भारत का केन्द्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और अमेरिका का केन्द्रीय बैंक है 'फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका'।
8. **अन्तर्राष्ट्रीय बैंक** – द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मेट्रिक लेन-देन और राष्ट्रों को विकास ऋणों आदि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं बैंकों का गठन हुआ है, इसमें प्रमुख हैं – अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, एशियाई विकास बैंक आदि महत्वपूर्ण हैं।

बैंक की मुख्य प्रवृत्तियाँ

1. आज बैंकिंग प्रणाली सामाजिक रूप से प्रयोजन मूलन बनकर आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में उभर चुकी है। इसलिये प्राथमिकताएँ प्राप्त क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह हुआ है।
2. गरीबी उन्मूलन कार्य के साथ बैंकिंग का एकीकरण हो चुका है।
3. ग्रामीण जनता में बचत की आदत बढ़ी है।
4. ऋण के भौगोलिक नियोजन की अपेक्षा क्षेत्रगत नियोजन महत्वपूर्ण बन गया है।
5. बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
6. बैंकिंग उद्योग को गैर बैंकिंग उद्योग से अत्यधिक प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ रही है।
7. बैंकिंग के तीव्र विस्तार ने अनेक तनाव व चुनौतियों को जन्म दिया है। अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी संख्या में स्टॉक की भर्ती व उनका प्रशिक्षण विशेषकर ग्रामीण अभिमुखता प्रदान करना।
8. बैंकिंग के भौगोलिक विस्तार के अन्तर्गत 'समेकन' का चरण उत्पन्न होता है। एक और ग्रामीण क्षेत्र में बैंक रहित स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जाता है, वही शहरी एवं महानगरीय शाखाओं को खोलने में प्रदर्शित आवश्यकता तथा वित्तीय क्षमता का ध्यान रखा गया है।

भारत में बैंक

1. वर्तमान में कुल 88 बैंक भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
2. सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से 28 वाणिज्यिक हैं, जिसमें आई.डी.बी.आई. बैंक भी शामिल है।
3. राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी तक 20 थी, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद घटकर 19 रह गयी।
4. निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है।

Please cite this Article as : मंजुला मालसे and डॉ. रेखा आचार्य , महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान – एक अध्ययन : Indian Streams Research Journal (MAY ; 2012)

5. वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की 49 फीसदी इक्विटी निजी क्षेत्रों द्वारा धारण की जा सकती है।
6. सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा किये गये बैंकिंग कारोबार में राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिस्सा 67 प्रतिशत है।
7. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये व्यावसायिक कारोबार में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा 48 प्रतिशत है।
8. निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है।
9. वर्तमान में कुल 88 बैंक भारत में कार्य कर रहे हैं। जिसमें से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।

राष्ट्रीय बैंकिंग (1969 से आज तक)

क्षेत्रीय असमानता दूर करने ग्रामीण व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में वृद्धि बचत राशियों को जुटाना तथा कृषि एवं सम्बन्ध उपेक्षित दोनों को लाभान्वित करने के लिये ऋण की दिशा पुनः निर्धारित करने हेतु 10 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग विधान की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1 दिसम्बर 1969 से लीड बैंक योजना आत्म हुई और 1977 में बैंकों ने 11 जिला ऋण योजनाओं का पहला दौर आरंभ किया।

शोध प्रणाली

प्रस्तुत शोध में निदर्शन विधि का उपयोग किया गया है, क्योंकि मूूू के 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से उपरी तौर पर 50 हितग्राही महिलाओं का चुना किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में मूूू तहसील की विभिन्न बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना एवं अन्तोदय योजना के अंतर्गत हितग्राहीयों को ऋण दिया गया।

तालिका क्र. 1

आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	20-25	07	14
2	25-30	23	64
3	30-35	15	30
4	35-40	05	25
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता महिलाओं में 20-25 प्रतिशत वर्ष की आयु की के बीच की 14 प्रतिशत महिलायें हैं। 25-30 वर्ष आयु वर्ग की 64 प्रतिशत महिलायें हैं, 30-35 आयु वर्ग की 3 प्रतिशत महिलायें तथा 35-40 आयु वर्ग की 25 प्रतिशत महिलायें हैं, तालिकानुसार 25-30 आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

तालिका क्र. 2

परिवार के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त	11	22
2	एकांकी	39	78
	कुल	50	100

उपर्युक्त सारणी द्वारा उल्लेखित होता है, कि संयुक्त परिवारों का 22 प्रतिशत है तथा एकांकी परिवारों का 78 प्रतिशत है, अर्थात् तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि एकांकी परिवारों में रहने वाली महिलाओं द्वारा सर्वाधिक ऋण लिया गया है।

तालिका क्र. 3

धर्म के आधार पर तालिका

क्र.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दु	44	88
2	मुस्लिम	05	10
3	सिक्ख	00	0
4	ईसाई	00	0
5	अन्य	01	02
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि हिन्दु धर्म की महिलाओं का 88 प्रतिशत है मुस्लिम महिलाओं का 10 प्रतिशत है क्या अन्य 2 प्रतिशत है।

Please cite this Article as : मंजुला मालसे and डॉ. रेखा आचार्य , महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान – एक अध्ययन : Indian Streams Research Journal (MAY ; 2012)

तालिका क्र. 4

शिक्षा एवं जाति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति की साक्षर महिलाओं की संख्या	08	16	अनुसूचित जाति की निरक्षर महिलाओं की संख्या	10	20
2	अनुसूचित जनजाति की साक्षर महिलाओं की संख्या	02	04	अनुसूचित जनजाति की निरक्षर महिलाओं की संख्या	01	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग की साक्षर महिलाओं की संख्या	10	20	अन्य पिछड़ा वर्ग की निरक्षर महिलाओं की संख्या	01	02
4	सामान्य वर्ग की साक्षर महिलाओं की संख्या	18	36	सामान्य वर्ग की निरक्षर महिलाओं की संख्या	00	00
	कुल	38	76		12	24

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की साक्षर महिलाओं का 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की 20 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की साक्षर महिलाओं का 4 प्रतिशत है तथा निरक्षर महिलाओं का 2 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग की साक्षर महिलाओं का 20 प्रतिशत है तथा निरक्षर महिलाओं का 2 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग की साक्षर महिलाओं का 36 प्रतिशत है तथा सामान्य वर्ग में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

तालिका क्र. 5

वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	43	86
2	अविवाहित	01	02
3	विधवा	06	12
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता महिलाओं में विवाहित महिलाओं का 86 प्रतिशत तथा अविवाहित महिलाओं का 2 प्रतिशत तथा विधवा महिलाओं का 12 प्रतिशत है। चूंकि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि विवाहित महिलाओं का बैंक द्वारा आसानी से ऋण सुलभ होता है।

तालिका क्र. 6

आर्थिक समृद्धि व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	व्यवसाय के साथ आर्थिक समृद्धि का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	पशुपालन द्वारा	14	28
2	निजी व्यवसाय द्वारा	30	60
3	मजदूरी द्वारा	06	12
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि 28 प्रतिशत है। व्यवसाय द्वारा 60 प्रतिशत, मजदूरी द्वारा 12 प्रतिशत आर्थिक समृद्धि दृष्टव्य है। अतः व्यवसाय द्वारा आर्थिक समृद्धि 60 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 7

योजना का विवरण के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)	24	48
2	एस.जी.एस.वाय (व्यक्तिगत)	20	40
3	अन्त्योदय योजना	06	12
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि 48 प्रतिशत उत्तरदाता महिला द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत ऋण लिया गया। 40 प्रतिशत महिला उत्तरदाता द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना पर ऋण लिया गया तथा 12 प्रतिशत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत महिलाओं द्वारा ऋण लिया गया।

चूंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा बिना किसी शर्त के बिना किसी वस्तु को गिरवी रखे बिना ही बैंक लोन प्राप्त हो रहा था, इसलिये सबसे अधिक ऋण प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत लिया गया।

तालिका क्र. 10

परेशानियों (बैंक कार्य प्रणाली) के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	परिशानियों का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कागजी कार्यवाही अधिक	31	62
2	समय अधिक	08	16
3	पूर्ण भुगतान नहीं होता	11	22
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका में बैंक द्वारा कार्यवाही के आधार पर उत्तरदाता द्वारा दिये गये उत्तर में कागजी कार्यवाही का 62 प्रतिशत है तथा समय अधिक लगा इसका 16 प्रतिशत है। पूर्ण भुगतान नहीं होता इसका 22 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 11

ऋण प्राप्त के उपरान्त आर्थिक समृद्धि का वर्गीकरण

क्र.	ऋण प्राप्त के उपरान्त आर्थिक स्थिति का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	29	58
2	नहीं	03	06
3	सामान्य	18	36
	कुल	50	100

ऋण प्राप्त के उपरान्त 58 प्रतिशत महिला उत्तरदाता ने कहा कि आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 36 प्रतिशत उत्तरदाता की स्थिति में सामान्य सुधार तथा 6 प्रतिशत उत्तरदाता ने नहीं कहा।

चूंकि बैंक योजनाओं के माध्यम से महिला छोटे-छोटे स्वयं के उद्योग खोल पाने में सक्षम रही हैं, लेकिन किसी कारणवश इन उद्योगों का न चल पाने की स्थिति सामान्य रही तथा बिल्कुल ही कम लाभ प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत कम रहा।

तालिका क्र. 12

महिलाओं के लाभ का वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	जागरूकता की कमी	19	38
2	अनायास भय	17	34
3	परिवार का भार	14	28
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि महिलायें जागरूकता की कमी की वजह से लाभ नहीं ले पा रही हैं।

Please cite this Article as : मंजुला भालसे and डॉ. रेखा आचार्य , महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान – एक अध्ययन : Indian Streams Research Journal (MAY ; 2012)

तालिका क्र. 13

भुगतान स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	भुगतान की स्थिति का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	बकाया	14	28
2	पूर्व भुगतान	36	72
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि 72 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ऋण का भुगतान समय पर कर दिया गया तथा 28 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह भुगतान बकाया रखा गया है।

चूंकि भुगतान ना करना इसमें कई कारण हो सकते हैं चूंकि व्यवसाय का विसर्त ना चलना या फिर कुछ स्वयं की आर्थिक परिशानी इस बात का मुख्य कारण बन जाती है।

तालिका क्र. 14

महिलाओं के लिये लाभकारी के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	आत्मविश्वास में वृद्धि	16	32
2	महिलाओं को रोजगार	11	22
3	परिवार की सहायता	23	46
	कुल	50	100

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि ऋण प्राप्ति ने महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि की है। आत्मविश्वास में वृद्धि का 32 प्रतिशत है। महिलाओं को रोजगार के लिये 22 प्रतिशत है तथा परिवार की सहायता 46 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि महिला का प्रथम उद्देश्य अपने परिवार की समृद्धि तथा परिवार के लालन-पालन से संबंधित होता है, भले ही वह कोई भी उद्योग को अपनाये लेकिन उसकी अपनी आर्थिक समृद्धि उसके अपने परिवार से ही जुड़ी रहती है।

सारांश

प्राचीनकाल में यदि हम नारी की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो वैदिक काल नारी स्वतंत्रता तथा निष्ठा का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है तथा धर्मयुग के पश्चात् मुगल काल तथा धर्मशास्त्र काल नारी के अस्तित्व, उसकी आत्मनिष्ठा, उसकी स्वतंत्रता का पतन का काल कहा जा सकता है। परंतु भारतीय नारी इस सबके परे थी, वह कठिनाईयों में भी अपने आपको सशक्त करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ थी।

महिलायें अधिकांशतः अपने आप को सशक्त करने के साथ-साथ पारिवारिक सहायता के लिए भी प्रयासरत दिखी तथा ग्रामीण महिलायें अपने छोटे उद्यमों के प्रति बहुत ही उत्साहित दिखी। योजनायें संचालित होने के बाद महिलाओं ने अधिकतम 2001 से 2007 के बीच ऋण प्राप्त किये तथा बैंकों द्वारा वितरित किये जाने वाले ऋणों में सबसे अधिक ऋण प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वितरित किया गया।

पशुपालन सब्जी विक्रेता, किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर टैचिंग क्लासेस, सिलाई क्लासेस चलाने हेतु महिलाओं ने अधिक ऋण प्राप्त किये। महिलाओं के लिये वास्तविक रूप से आर्थिक सशक्त होने के माध्यम के रूप में इन बैंक योजनाओं का महत्वपूर्ण हाथ माना जा रहा है। तथा शीघ्र अध्ययन में हमारे द्वारा अवलोकन किया गया कि महिलायें इस प्रकार की ऋण सुविधा द्वारा प्रसन्न दिखाई दी।

लेकिन निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बैंक द्वारा जो भी योजनायें चलाई जा रही हैं उनका लाभ महिला अपना सशक्त आर्थिक आधार बनाने के लिये कर रही हैं तथा सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर हैं। यह सशक्तिकरण उनकी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

1. शोध के अंतर्गत अवलोकन के पश्चात् 64 प्रतिशत महिलायें जो कि 25 से 0 आयु वर्ग की थी उन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया।
2. 78 प्रतिशत एकांकी परिवारों की महिलायें जिन्होंने बैंक ऋण योजनाओं का लाभ उठाया
3. शोध के अंतर्गत 88 प्रतिशत हिन्दू परिवारों की महिलाओं ने बैंक ऋण योजनाओं द्वारा अपना आर्थिक सशक्तिकरण किया।
4. 40 से 80 हजार आवेदित ऋण लेने वाली हितग्राही महिलाओं का 40 प्रतिशत है, जो कि अधिक है।
5. सबसे अधिक 48 प्रतिशत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के दौरान ऋण लिया गया।
6. ऋण प्राप्ति के बाद अधिक समृद्धि 58 प्रतिशत थी जबकि 6 प्रतिशत द्वारा आर्थिक समृद्धि को अनुभव नहीं किया गया।
7. महिलाओं के आत्मविश्वास में 46 प्रतिशत वृद्धि तथा महिलाओं की 22 प्रतिशत रोजगार मिलने की संभावना पैदा हुई
8. जागरूकता की कमी 38 प्रतिशत तथा अनायास भय की वजह से 24 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सका।
9. भुगतान स्थिति का प्रतिशत 72 प्रतिशत है तथा केवल 28 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया गया।
10. परेशानियों का विवरण निष्कर्ष निकलाने पर हम पाते हैं कि कागजी कार्यवाही में अधिक समय लगा।
11. बैंक की कार्यप्रणाली में देखे तो 72 प्रतिशत महिलाओं को बैंक की कार्यप्रणाली अच्छी लगी।

Please cite this Article as : मंजुला मालसे and डॉ. रेखा आचार्य , महिलाओं के आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास में बैंकिंग का योगदान – एक अध्ययन : Indian Streams Research Journal (MAY ; 2012)

सुझाव

1. बैंकिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि बैंक ऋण सही एवं पूरा प्राप्त हो सके।
2. बैंक द्वारा जो भी कागजी कार्यवाही होती है, उसमें कम से कम कागजी कार्यवाही का प्रावधान हो लेकिन वह बैंकिंग व्यवस्था को संतुष्ट करने वाली है।
3. महिला जो कि ऋण के लिए आवेदन करती है उसके साथ बैंक कर्मचारियों का व्यवहार सहयोगपूर्ण रहना चाहिये।
4. बैंक ऋण को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे हितग्राही को स्थायी व्यवसाय प्राप्त हो।
5. बैंक की महिला हितग्राही के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वह स्वयं के व्यवसाय के लिये पारंगत हो सके।
6. बैंक द्वारा महिला हितग्राही को पूर्णतः जानकारी के लिये अलग से विभाग बनाना चाहिये।
7. योजना का क्रियान्वयन करते समय बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्णतः सावधानी बरती जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा हरिशंकर सिंह, (2001) मुद्रा एवं बैंकिंग, नई दिल्ली
2. होरा आशारानी (1983) भारतीय नारी दशा एवं दिशा नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
3. कांत मीरा (1994) अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक और पत्रकारिता क्लासिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली
4. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ (2001) सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन (आठवां संस्करण) जवाहर नगर, दिल्ली
5. रानी आशु (1999) महिला विकास कार्यक्रम, इनस्टी पब्लिशर्स, जयपुर
6. नैयर रेणुका (1990) नारी स्वतंत्रता के बदलते रूप
7. सहाय सुषमा (1990) वूमन एण्ड डेवलपमेंट
8. शर्मा प्रज्ञा (2001) कार्यशील महिलाएँ (प्रथम संस्करण) पोस्टर पब्लिशर्स, जयपुर
9. Basu al (1997) Micro Finance Emerging Challeges, Taga MC Grow Hill Publication
10. Sahaya Sushma (1998) Women an Empowerment Discovery publishing house Delhi
11. परमार तारा, (2008, फरवरी, अश्वस्त) भारतीय नारी की दशा एवं दिशा
12. भारतीय अर्थव्यवस्था, (2007)
13. प्रतियोगिता दर्पण (फरवरी 2007)
14. क्रॉनिकल (मार्च, 2008)